NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 18 Sep, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : Governance & International Relations/ Prelims**	टैरिफ विवाद के बीच, पीएम ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया
Page 04 & 12 **Syllabus : GS 2 & 3 : International Relations & Indian Economy / Prelims**	यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी को उन्नत करने के लिए तैयार
Page 08 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims**	अटके हुए विधायी कार्य के बाद एक न्यायिक प्रेरणा
Page 08 **Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims**	गाजा में नरसंहार: भारत को इजरायल के अत्याचारों के खिलाफ बोलना चाहिए
Page 09 **Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims**	आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय के बारे में कड़वी सच्चाई
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 2 : International Relations**	गीजर काउंटरों को अनुमान नहीं लगाने दें, ईरान की कार्रवाइयों को आकार दें

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01: GS 2 : Governance & International Relations / Prelims

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी को अपनाने और स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने का हालिया आह्वान आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में भारत के प्रयास को उजागर करता है। यह घोषणा मध्य प्रदेश के धार में पहले **पीएम मित्र पार्क** की नींव के साथ हुई, जो टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार तनाव के बीच थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य पहल की शुरुआत और सीमा पार आतंकवाद पर भारत के मजबूत रुख को दोहराया गया।

Amid tariffs row, PM pushes local production

Indians must embrace Swadeshi, as it will help in development of the country, says Modi

PM says he will urge State governments to put up signs in every shop detailing Indian products

He also hails the armed forces which 'brought Pakistan to its knees' during Operation Sindoor

Mehul Malpani
BHOPAL

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday urged citizens to buy only made-in-India products and traders to sell only indigenously manufactured goods as he laid the foundation for the country's first PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) park in Madhya Pradesh's Dhar district.

His remarks came a day after the latest round of talks on an elusive India-U.S. trade agreement, amid tensions over U.S. tariffs on Indian products, even as U.S. President Donald Trump wished Mr. Modi for his 75th birthday.

"This is the season of festivals, and at this very time, we must remember the mantra of Swadeshi and incorporate it into our lives. I have a humble request to my 140 crore fellow countrymen: whatever you buy, it should be made in our country," Mr. Modi said in Dhar's Bhainsola.

Saying he wants to build a developed India by 2047, he added, "Whatever our businesspersons sell must be made in our country. Now we must make Swadeshi the foundation of a developed India. This will happen when we proudly buy products made in the country. We must first determine whether the product is made in the country. When we do this, our money remains in the country and leads to the development of the country."

Big push: Prime Minister Narendra Modi during the launch of the PM MITRA Park at Dhar in Madhya Pradesh on Wednesday. PTI

Referring to Operation Sindoor, which began with Indian air strikes on terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir on May 7, Mr. Modi said the Armed Forces had "brought Pakistan to its knees in the blink of an eye."

"Just yesterday, the nation and world saw a Pakistani terrorist speaking of his ordeal while crying," he said, alluding to a viral video of Jaish-e-Mohammad commander Ilyas Kashmiri, who claimed that the family of group chief Masood Azhar was "torn into pieces on May 7".

"Terrorists from Pakistan had destroyed the *sindoor* [vermillion] on our sisters. We have destroyed terrorist hideouts through Operation Sindoor. This is new India, it is not scared of anyone's nuclear threats. It enters [the enemy's] house and strikes," the Prime Minister said.

'Buy Swadeshi'

He also noted that the new GST rates will come into effect from September 22, coinciding with the first day of Navratri. "We need to launch a campaign promoting Swadeshi. I will urge the State government to put up signs in every shop detailing Swadeshi goods. Buyers will also know that they are buying Swadeshi," he added.

Mr. Modi launched the Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan (SNSPA), a Union government initiative aimed at improving women's health through comprehensive screenings and services.

"Its goal is to ensure that no woman falls victim to any disease due to lack of information. There are diseases that women are most vulnerable to. It's crucial to detect these diseases early. Serious diseases like cancer can be detected early. The women of our country continue to bless me. Therefore, these programs are for them," he said, urging women to avail free check-up and medication services. The campaign will run until Gandhi Jayanti on October 2.

The PM MITRA park in Dhar is one of seven such establishments approved by the Union Ministry of Textiles.

The other sites are in Tamil Nadu's Virudhnagar, Telangana's Warangal, Gujarat's Navasari, Karnataka's Kalaburagi, Uttar Pradesh's Lucknow, and Maharashtra's Amravati.

Based on the 5F theme – farm to fibre to factory to fashion to foreign – the initiative aims to boost India's textile manufacturing and exports. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav recently said proposals worth more than ₹23,000 crore have been received from 114 textile companies for the Dhar park.

BIRTHDAY GREETINGS
» PAGE 5

करंट अफेयर्स के मुख्य आयाम

1. स्वदेशी और व्यापार नीति

- प्रधानमंत्री ने नागरिकों से केवल मेड इन इंडिया उत्पादों को खरीदने और व्यापारियों से केवल मेड इन इंडिया उत्पादों को बेचने का आग्रह किया।
- घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर पैसा रखने पर जोर देने से एमएसएमई, कारीगरों, स्थानीय उद्योगों **को बढ़ावा →।**
- संदर्भ: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में गतिरोध और टैरिफ विवाद आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को उजागर →।

2. पीएम मित्र पार्क

- **पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) योजना**: राज्यों में सात पार्कों को मंजूरी दी गई।
- मध्य प्रदेश के धार पार्क में सबसे पहले उड़ान भरी गई है। ₹23,000+ करोड़ के निवेश प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

- **5F दृष्टि**: फार्म → फाइबर → फैक्टरी → फैशन → विदेशी।
- उद्देश्य: भारत के कपड़ा निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, रसद लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना।
- स्टेटिक लिंक: भारत का कपड़ा उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में ~2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।

3. महिला स्वास्थ्य पहल

- स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (एसएनएसपीए) **का शुभारंभ**: 2 अक्टूबर तक मुफ्त जांच और दवाएं।
- एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) और एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) **के लिंक के** माध्यम से प्रारंभिक पहचान → माध्यम से कैंसर जैसी बीमारियों से निपटता है।
- परिवार और राष्ट्रीय विकास के लिए एक नींव के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करता है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा कोण

- प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन **सिंदूर (7 मई, 2025)** - पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारतीय हवाई हमलों का संदर्भ दिया।
- संदेश: भारत का सक्रिय आतंकवाद विरोधी रुख, "न्यू इंडिया" परमाणु खतरों से विचलित नहीं है।
- स्टैटिक लिंक: भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट 2019, आदि।

स्टेटिक लिंकेज (प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य)

- **कपड़ा उद्योग**: प्रमुख केंद्र - सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, भीलवाड़ा।
- **वस्त्र से संबंधित योजनाएं**: एसआईटीपी, आरओएससीटीएल, संशोधित टीयूएफएस, समर्थ, पीएम मित्र।
- **व्यापार नीति**: विश्व व्यापार संगठन, टैरिफ विवाद, अमेरिका, यूरोपीय संघ, आसियान के साथ एफटीए पर भारत का रुख।
- **महिला स्वास्थ्य मिशन**: पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)।
- **सुरक्षा संचालन**: "ऑपरेशन सिंदूर" की तुलना पहले के "ऑपरेशन विजय" (कारगिल) और "ऑपरेशन मेघदूत" (सियाचिन) से की जाती है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **अवसर**:
  - स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से वस्त्रों में (कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता)।
  - आयात निर्भरता को कम करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है।
  - कूटनीतिक और सैन्य रूप से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को बढ़ाता है।
- **चुनौतियाँ**:
  - सस्ते आयात (जैसे, चीनी सामान) की तुलना में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करना।
  - टैरिफ युद्धों के बीच व्यापार प्रतिशोध का जोखिम।
  - जमीनी स्तर पर महिला स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
  - वैश्विक व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ राष्ट्रवाद से प्रेरित खपत को संतुलित करना।

शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध निष्कर्ष

प्रधानमंत्री का धार संबोधन आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को आपस में जोड़ता है। जबकि **पीएम मित्र पार्क** औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में एक ठोस कदम प्रदान करते हैं, स्वदेशी **आह्वान** 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रभावी व्यापार कूटनीति और कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: पीएम मित्र योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य खेत से लेकर विदेश तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है।
2. विभिन्न राज्यों में सात पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दी गई है।
3. इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: स्वदेशी पुश और मेगा टेक्सटाइल पार्क 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के मार्ग का अभिन्न अंग हैं। हाल ही में सरकार की पहलों के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 शब्द)**

Page 04 & 12 : GS 2 & 3 : International Relations & Indian Economy / Prelims

यूरोपीय संघ (ईयू) ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन में सहयोग को गहरा करने के लिए **"नया रणनीतिक ईयू-भारत एजेंडा"** जारी किया है । यह **भारत-यूरोपीय संघ एफटीए** (मुक्त व्यापार समझौते) के लिए चल रही बातचीत के बीच आया है। हालांकि, **रूस से भारत का तेल आयात** और रूसी **सैन्य अभ्यास में भागीदारी** ब्रसेल्स में विवाद का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही, भारत **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के साथ एफटीए वार्ता** कर रहा है, जिसमें बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी बहु-संरेखण रणनीति पर प्रकाश डाला गया है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

EU-India partnership set for upgrade

EU's top diplomat Kaja Kallas releases strategic agenda on trade, technology, security, defence and climate; however, India's military exercises with Russia and its continued purchase of Russian oil are seen in Brussels as potential obstacles to the deepening of the relationship with New Delhi

Sriram Lakshman
LONDON

The European Union has set out a plan to upgrade its strategic ties with India, even as it warned that India's military exercises with Russia and its purchase of Russian oil are risks to the growing strategic ties between Brussels and New Delhi.

The European Commission and the EU's top diplomat Kaja Kallas released 'A New Strategic EU-India Agenda' on Wednesday in Brussels, and urged the European Parliament and Council (i.e., the heads of member states) to adopt it.

Ms. Kallas called India a "crucial" partner for the EU, as she outlined the strategy that encompassed trade, technology, security, defence and climate. She was speaking at a televised press conference in Brussels on Wednesday.

The document declared that "the EU and India have the potential and determination to shape one of the defining partnerships of the 21st century".

Brussels and New Delhi are in the midst of negotiating a free trade agreement (FTA), with the EU's trade chief Maroš Šefčovič visiting New Delhi last week for talks with Commerce Minister Piyush Goyal.

"We are also negotiating an agreement of exchange of classified information and deepening ties between defence industry [sic]," Ms. Kallas said, adding that there were hesitations here among the College of Commissioners (comprised of Commissioners from the 27 EU countries).

With Russia escalating its attacks on Ukraine in recent weeks, the Europeans are grappling with how to navigate New Delhi's closeness to Moscow.

"India's participation in Russia's military exercises and its purchase of Russian oil stand in the way of closer ties, because ultimately, our partnership is not only about trade, but also about defending rules-based international order," Ms. Kallas said.

The European Commission's High Representative for Foreign Affairs Kaja Kallas and European Commissioner for Trade Maroš Šefčovič at a press conference in Brussels, Belgium on Wednesday. REUTERS

"It is of utmost importance to the EU that any enablement of the war be curtailed," the strategy document says.

The negotiations with New Delhi would address these challenges with the aim of adopting a joint roadmap at the next EU-India summit in early 2026, according to Ms. Kallas.

Prime Minister Narendra Modi said he was "delighted" by the adoption of the new strategic document. "We remain committed to an early and peaceful resolution of the Ukraine conflict," he said, reflecting on his phone call on Wednesday with European Commission President Ursula von der Leyen.

India and the EU have been seeking to bolster ties in the face of increasing geopolitical uncertainty and challenges in their trade relationships with the U.S.

Trade between India and the EU has grown over 90% in the last decade, Mr. Šefčovič said at Wednesday's press conference, but the two sides had just "scratched the surface", according to the Commissioner. Brussels and New Delhi are hoping to conclude a trade deal by the end of the year.

Mr. Šefčovič said he was in frequent touch with Mr. Goyal but wished that there had been "more progress" on talks during his visit to New Delhi last week. He also said that Indian trade negotiators have a reputation for being "tough".

Tariff barriers

On the question of agricultural tariffs, Mr. Šefčovič said that the issue was not about numbers but rather about whether what was being offered was commercially meaningful, after taking into account tariff and non-tariff barriers. He cited India's Qualitative Control Orders (QCOs) as an example and said they were something the EU should consider in its negotiations.

The 14th round of trade talks is due to take place in Brussels from October 6-10.

Quizzed specifically on India's participation in the recent Zapad-2025 military exercises led by Russia, Ms. Kallas said she had spoken to External Affairs Minister S. Jaishankar on Tuesday. She reiterated that exercises with Russia and buying oil were issues to the relationship.

"The question is always whether we leave this void to be filled by somebody else. So we try to fill it ourselves," she said in response to the question on cooperation with India. She responded similarly, when quizzed on India's apparent détente with China.

The College of Commissioners had agreed that the EU should deepen ties with India to "not really push them into Russia's corner".

Ms. Kallas cited the principle of 'nothing is agreed until everything is agreed' several times, including when asked about how the trade talks would be impacted if India did not take on board the EU's concerns regarding Russia.

प्रमुख वर्तमान घटनाक्रम

1. रणनीतिक एजेंडा 2025+

- यूरोपीय संघ ने भारत को 21वीं सदी की परिभाषित साझेदारी को आकार देने के लिए एक "महत्वपूर्ण भागीदार" कहा।
- फोकस: **व्यापार, तकनीक, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु**।
- 2026 में अगले यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन **में संयुक्त रोडमैप की उम्मीद है**।

2. भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार ↑ पिछले दशक में 90%।
- वर्तमान मुद्दा: **टैरिफ बाधाएं, क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश),** और **कृषि में बाजार पहुंच**।
- **वार्ता का 14वां दौर** ब्रुसेल्स में निर्धारित (6-10 अक्टूबर, 2025)।
- यूरोपीय संघ "व्यावसायिक रूप से सार्थक" प्रस्तावों पर जोर देता है, न कि केवल टैरिफ में कमी की संख्या।

3. रूसी कोण

- **यूरोपीय संघ की चिंताएँ:**
  - भारत द्वारा **रूसी तेल की खरीद** (रियायती दरों पर)।
  - रूस के साथ **जैपड-2025 सैन्य अभ्यास** में भागीदारी।
- यूरोपीय संघ को डर है कि यह "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करता है।
- साथ ही, यूरोपीय संघ भारत को "रूस के कोने में धकेलने" से रोकना चाहता है।

4. भारत का बहु-संरेखण

- भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के साथ एफटीए **की खोज कर रहा है** (जिसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया शामिल हैं)। पहला दौर **नवंबर 2025** की उम्मीद है।
- एक साथ वार्ता: **यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, आसियान (समीक्षा)** भारत की विविध व्यापार रणनीति का हिस्सा →।

स्थैतिक संबंध

- **यूरोपीय संघ-भारत संबंध:**
  - रणनीतिक साझेदारी: 2004।
  - यूरोपीय संघ भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** (कुल व्यापार का ~11%) है।
  - सहयोग के क्षेत्र: कनेक्टिविटी पार्टनरशिप (2021), जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, अनुसंधान और नवाचार (क्षितिज यूरोप)।
- **ETA पृष्ठभूमि**:
  - भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) वार्ता 2007 में शुरू हुई, 2013 में रुकी हुई, 2022 में पुनर्जीवित हुई।
- **EAEU**:
  - रूस के नेतृत्व में एक सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार, 2015 में स्थापित।
  - मुख्यालय: मास्को।
- **व्यापार नीति संदर्भ:**
  - भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया (ईसीटीए) के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - चल रही वार्ता: यूके, ईयू, कनाडा, ईएईयू।

मुख्य आयाम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- यूरोपीय संघ-भारत अभिसरण: जलवायु परिवर्तन, हिंद-प्रशांत, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, हरित संक्रमण।
- विचलन: रूस नीति, मानवाधिकार, कृषि शुल्क।
- संतुलन अधिनियम: भारत को यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को नेविगेट करना चाहिए।

बचत

- यूरोपीय संघ के साथ एफटीए निर्यात (कपड़ा, फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स) को बढ़ावा देने →।
- यूरोपीय संघ कृषि, डेयरी, सेवाओं में पहुंच चाहता है।
- गैर-टैरिफ बाधाएं (क्यूसीओ) → डब्ल्यूटीओ संगतता समस्याएं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

सुरक्षा और रक्षा

- सूचना-साझाकरण समझौते और रक्षा उद्योग सहयोग के लिए प्रस्ताव।
- यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **नियम-आधारित व्यवस्था** को बनाए रखने में एक भागीदार के रूप में हो।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **अवसर**:
  - यूरोपीय संघ-भारत एफटीए अमेरिका और चीन से परे भारत के निर्यात बाजारों में विविधता ला सकता है।
  - रक्षा और तकनीकी सहयोग भारत के "आत्मनिर्भर भारत" के अनुरूप है।
  - जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करती है।
- **चुनौतियाँ**:
  - यूरोपीय संघ का रूस रुख बनाम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बहु-संरेखण नीति।
  - टैरिफ और गैर-टैरिफ असहमति।
  - यूरोपीय संघ की मानवाधिकार शर्तें एफटीए को जटिल बना सकती हैं।

निष्कर्ष

उन्नत यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा बदलती भू-राजनीति के बीच एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के साथ साझेदारी करने के यूरोप के इरादे का संकेत देता है। जबकि रूस पर मतभेद बने हुए हैं, दोनों पक्ष व्यापार, जलवायु और सुरक्षा में संबंधों को मजबूत करने के मूल्य को पहचानते हैं। भारत के लिए, व्यावहारिक आर्थिक लाभ के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करना यह निर्धारित करेगा कि क्या भारत-यूरोपीय संघ एफटीए और व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2026 तक वास्तविकता बन जाएगी।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: यूरोपीय संघ (ईयू) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।
2. वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं।
3. यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क संघ का हिस्सा बना हुआ है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC Mains Paper Practice Question

प्रश्न : . भारत के निर्यात, रोजगार और एमएसएमई क्षेत्र पर प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संभावित आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। **(150 शब्द)**

Page 08 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अनुच्छेद 200 **और** अनुच्छेद 201 **के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई रोकने के मुद्दे को संबोधित किया है**। **तीन महीने की समय सीमा** निर्धारित करके, न्यायालय ने विधायी पक्षाघात को रोकने की मांग की। इसने शक्तियों के पृथक्करण, संवैधानिक प्राधिकारियों के विवेक और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर बहस शुरू कर दी है।

उठाए गए प्रमुख मुद्दे

1. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की भूमिका

- **4. विकल्प:**
  1. विधेयक को स्वीकृति प्रदान कीजिए।
  2. सहमति रोकें।
  3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में लौटाना।
  4. राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
- वाद-विवाद: क्या राज्यपाल को विवेक प्राप्त है या वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधा हुआ है?

A judicial nudge following stuck legislative business

The Supreme Court of India has heard arguments on the Presidential Reference in respect of the Governor's powers under Article 200 pertaining to the assent to Bills passed by the State legislature. Earlier, a two-judge Bench, headed by Justice J.B. Pardiwala, had fixed a timeline of three months for the Governor to take a final decision on a Bill submitted to him for assent. The same timeline was made applicable to the President of India also.

The time limit fixed by the Court has raised eyebrows in the government as well in the media. The general refrain from a section of the media was that the Court cannot direct the Governor or the President, who are high constitutional authorities, to act within a specified time when the Constitution does not have any such time frame. The government had also taken this line of argument in the Court.

Reiteration of a recognised principle

Article 200 of the Constitution has four options for the Governor when a Bill is presented to him after being passed by the State legislature. These options are to assent to the Bill; to withhold assent; return the Bill to the Assembly with a request to reconsider the Bill as a whole or certain clauses, or reserve it for the consideration of the President.

A very important question which arose in the context of the Governor's role in dealing with a Bill after it is passed by the legislature is whether the Governor has any discretion in the exercise of any of the options mentioned above. Under Article 163, the Governor is required to exercise his functions only on the aid and advice of the Council of Ministers except in matters specified by or under the Constitution. The Court has, in cases from *Shamsher Singh vs State of Punjab* (1974), to *Nabam Rebia* (2016), made it clear that the Governor cannot perform any of his executive functions except on the advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. The Sarkaria Commission and Punchhi Commission too reiterated this well-recognised constitutional principle.

The point that has been emphasised in all the judgments of the Court and the judicial commissions is that the Governor is just a constitutional head and that the real executive power of the state is vested in the elected government. Therefore, the Governor cannot act independently.

So, the question of crucial importance in this context is whether the Governor, while exercising any of the options under Article 200, can act in his discretion. The answer to this question will become clear when we take a close look at the

P.D.T. Achary
is former Secretary General, Lok Sabha

The top court's move to fix a time limit for a Governor to take a final decision on a Bill must be interpreted as a move to smoothen the legislative process

Government of India Act, 1935. Section 75 of this Act is substantially the same as Article 200. Section 75 uses the words "the governor in his discretion" which means that giving assent or withholding it or sending the Bill back to the legislature or reserving it for the consideration of the Governor General is done by the Governor in his discretion.

This Section has been virtually reproduced in Article 200 but omits the words "in his discretion". This would show that the Constitution-makers wanted the Governor to exercise the power under Article 200 only on the advice of the Council of Ministers.

The issue of 'discretion'

The question of discretion of the Governor under Article 200 is one that has been dealt with by the Court in a number of cases. Surprisingly, the Court, in *Shamsher Singh*, discovered a discretionary power in the Governor under Article 200. It held that he must exercise it to the best of his judgement and should pursue a course which is not detrimental to the state.

But the Court, in *The State of Tamil Nadu vs The Governor Of Tamilnadu and Anr.* (2025), did not accept the idea of a Governor exercising his discretion in withholding assent or reserving the Bill for the consideration of the President. It says, "if the power to withhold assent to Bills or to reserve them for the consideration of the President is construed as falling within the exclusive discretionary domain of the governor who would be free to decide a course of action notwithstanding the aid and advice of the council of ministers it would have the potential of turning him into a super constitutional figure having the power to bring to a complete halt the operation of the legislative machinery in the state. The governor cannot be vested with such power...."

The Sarkaria Commission, while granting that, normally, in the discharge of the functions under Article 200, the Governor must abide by the advice of his Council of Ministers, said that in rare and exceptional cases, he may act in the exercise of his discretion especially when the provisions of the Bill are patently unconstitutional.

While divergence of opinion exists in Indian judicial decisions, according to D.D. Basu, the renowned constitutional authority, in the United Kingdom, the sovereign has no power to withhold a Bill without the advice of the Council of Ministers. The deliberate omission of the word 'discretion' in Article 200 of the Constitution of India compels the conclusion that this Article does not permit discretion of any kind by the Governor while dealing with a Bill passed by the legislature.

The next question is about the time limit prescribed by the Court within which the Governor and the President are required to take a final decision on a Bill. From the arguments made on behalf of the Union Government, it is clear that it has strong objections to the time limit. It is true that no time limit has been prescribed by Articles 200 or 201. It is obvious that the Court fixed the time limit because some of the Governors had sat on Bills for years together without exercising any of the options available under Article 200. The question is whether the Constitution permits such a course of action. It does not.

So, is there no remedy available to States whose important Bills go in limbo? When a Governor sits on Bills for years, should not the Union intervene and direct the Governor to act in accordance with the Constitution? Article 355 can be creatively interpreted to mean that the Union Government can intervene to ensure that the government of a State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Thwarting the legislative process by the Governor by sitting on Bills passed by the legislature for years creates a situation where in the government cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Article 355 imposes a duty upon the Union to direct the Governor to perform his constitutional duty under Article 200.

A remedy for what is now a reality

In no case has the Union intervened to direct a Governor to clear the Bills that he sat on for years. That has forced the Supreme Court to fix the time limit now. The Constitution makers could not have visualised such conduct on the part of the Governors. But now that it has become a reality, a remedy has to be found. By fixing the time limit, the Court has smoothened the legislative process.

The judgments in the two recent cases, namely, *State of Punjab vs Principal Secretary to the Governor* (2023) and *The State of Tamil Nadu vs The Governor Of Tamilnadu and Anr.* are in fact landmark judgments which struck a blow for federalism. Judges interpret the Constitution and clarify the legal ambiguities, and in that process also create new rules. Article 21 was a prisoner of the literal interpretation since 1950 (*A.K. Gopalan*) till the American doctrine of due process was imported into it and expanded its ambit in *Maneka Gandhi* (1978).

Therefore, it is quite out of place to argue that judges, by interpreting the existing provisions to meet a new situation which posed a serious challenge to the constitutional order, are amending the Constitution. The fallacy in this argument is too obvious to miss.

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)** → राज्यपाल को सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां संविधान स्पष्ट रूप से विवेक प्रदान करता है।
- **नबाम रेबिया (2016)** → राज्यपाल निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं।
- **पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023)** → राज्यपाल विधेयकों में अनिश्चितकाल के लिए देरी नहीं कर सकते।
- **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)** → सहमति को रोकने के विवेक को निरंकुश नहीं किया जा सकता है, अन्यथा राज्यपाल एक "सुपर-संवैधानिक" प्राधिकरण बन जाता है।

3. संविधान सभा का इरादा

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 (धारा 75) → राज्यपालों के विवेकाधिकार की अनुमति दी।
- अनुच्छेद 200 (भारतीय संविधान) → **जानबूझकर** "अपने विवेक से" वाक्यांश को हटा दिया।

- तात्पर्य: फ्रेमर्स चाहते थे कि राज्यपाल केवल मंत्रिस्तरीय सलाह पर कार्य करें।

4. समय सीमा विवाद

- संविधान अनुच्छेद 200/201 के तहत समयसीमा पर चुप है।
- सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर बैठे राज्यपालों के जवाब → **3 महीने** का समय तय किया है।
- सरकार की आपत्ति: न्यायपालिका संविधान में प्रदान नहीं की गई समयसीमा नहीं लगा सकती है।
- काउंटर: न्यायिक नवाचार सुचारू विधायी कामकाज सुनिश्चित करता है और संवैधानिक टूटने को रोकता है।

5. अनुच्छेद 355 के तहत संघ की भूमिका

- संघ का कर्तव्य: सुनिश्चित करें कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें।
- यदि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोकते हैं, तो यह संवैधानिक शासन का उल्लंघन करता है।
- संभावना: संघ राज्यपालों को कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने का निर्देश दे सकता है।

स्टेटिक लिंकेज (प्रीलिम्स पॉइंटर्स)

- **लेख:**
  - अनुच्छेद 163 → सहायता और सलाह सिद्धांत।
  - अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधेयकों को स्वीकृति →
  - अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा करना और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य →।
- **कमीशन**:
  - **सरकारिया आयोग** और **पुंछी आयोग** → राज्यपालों को आम तौर पर सलाह पर काम करना चाहिए, दुर्लभ विवेक केवल तभी जब विधेयक असंवैधानिक हो।
- **अवधारणाएं**:
  - शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक, संघवाद।

मुख्य प्रासंगिकता

राजनीति और शासन

- राज्यपाल की भूमिका: एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, बाधा नहीं।
- संघवाद **की रक्षा के रूप में न्यायिक हस्तक्षेप**।

न्यायतंत्र

- न्यायिक नवाचार: मेनका गांधी (1978) की तरह, न्यायालय ने व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार किया।
- इसी तरह, अनुच्छेद 200 के तहत समय-सीमा विधायी जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

संघवाद

- ऐसे मामले निर्वाचित राज्य सरकारों बनाम नियुक्त राज्यपालों **के बीच टकराव दिखाते हैं**।
- अदालत ने राज्यपाल के मनमाने विवेक को सीमित करके संघीय संतुलन को बरकरार रखा।

दैनिक समाचार विश्लेषण

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **SC के हस्तक्षेप के सकारात्मकता:**
  - विधायी पक्षाघात को रोकता है।
  - निर्वाचित सरकार की प्रधानता को मजबूत करता है।
  - संघीय भावना को मजबूत करता है।
- **चिंताएँ**:
  - न्यायपालिका समयसीमा निर्धारित करती है →व्याख्या और कानून के बीच धुंधली रेखा।
  - "न्यायिक अतिरेक" तर्क का जोखिम।

निष्कर्ष

पंजाब (2023) **और** तमिलनाडु (2025) **में सुप्रीम कोर्ट के फैसले** संघवाद की रक्षा करने और गवर्नर शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने **में ऐतिहासिक कदमों का प्रतिनिधित्व करते** हैं । एक समय सीमा लगाकर, न्यायालय ने एक व्यावहारिक संवैधानिक गतिरोध को संबोधित किया है। संविधान में संशोधन करना तो दूर, यह न्यायपालिका का एक उदाहरण है जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की गतिशील रूप से व्याख्या कर रही है। अंततः, राज्यपाल को **एक संवैधानिक प्रमुख बना रहना चाहिए, न कि राजनीतिक मध्यस्थ,** और न्यायालय का धक्का भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित कर सकता है:
1. विधेयक पर सहमति।
2. सहमति रोकें।
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना (धन विधेयकों को छोड़कर)।
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखिए।

उपरोक्त में से कौन सा सही है?
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 2 और 4

उत्तर : c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख बने रहना चाहिए, न कि राजनीतिक मध्यस्थ। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आलोक में, अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। **(150 शब्द)**

Page : 08 : GS 2 : International Relations / Prelims

संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग **ने** निष्कर्ष निकाला है कि इज़राइल **गाजा में नरसंहार** कर रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून में सबसे गंभीर आरोपों में से एक है। **अक्टूबर 2023 से महिलाओं और बच्चों सहित** 65,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या के साथ, निष्कर्ष **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)** और **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)** के समक्ष चल रहे मामलों को मजबूत करते हैं। जबकि वैश्विक निंदा बढ़ रही है, भारत ने अब तक इजरायल की सीधी आलोचना से परहेज किया है, जिससे उसकी विदेश नीति के रुख पर सवाल उठते हैं।

करेंट अफेयर्स आयाम

1. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- नवी पिल्ले के नेतृत्व में बहु-वर्षीय जांच की।
- नरसंहार के 5 में से 4 कृत्यों में इज़राइल को दोषी पाया गया:
  - एक समूह के सदस्यों की हत्या।
  - गंभीर शारीरिक/मानसिक नुकसान पहुंचाना।
  - समूह को नष्ट करने के उद्देश्य से कार्रवाई।
  - जन्म को रोकना।
- रिपोर्ट सीधे तौर पर इजरायली नेतृत्व को फंसाती है।

2. अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संदर्भ

- **आईसीजे (हेग)** इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले की सुनवाई →।
- **आईसीसी** → ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
- **नरसंहार कन्वेंशन** (1948) → नरसंहार को एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे के रूप में परिभाषित करता है।

Genocide in Gaza

India should speak up against Israel's atrocities

The UN Commission of Inquiry, after a multi-year investigation, has concluded that Israeli authorities have committed genocide in Gaza. The finding is hardly surprising as the world's leading rights organisations, including two Israeli groups, and genocide scholars, had already accused Israel of committing what is one of the gravest crimes in international law. Yet, the finding would lend weight to such reports and resonate before the International Court of Justice, which is hearing genocide charges against Israel, and the International Criminal Court, which has issued an arrest warrant for Prime Minister Benjamin Netanyahu. The UN Commission found "reasonable grounds" to conclude that four of the five genocidal acts – killing members of a community, serious bodily and mental harm, actions aimed at destroying the group, and preventing births – have been carried out since the war began following Hamas's October 7, 2023 attack. Israel, which denies allegations of genocide and war crimes, has killed at least 65,000 Palestinians in Gaza in 23 months, many of them women and children. "The responsibility for these atrocity crimes lies with Israeli authorities at the highest echelons who have orchestrated a genocidal campaign with the specific intent to destroy the Palestinian group in Gaza," says the panel's leader, Navi Pillay.

It is tragically ironic that Israel, a nation built by the survivors of the Shoah, is committing genocide against Palestinians. On the day the UN Commission released its report, Israel launched yet another ground offensive in the famine-stricken Gaza City. Israel's responses to reports of war crimes and mass killings have invariably been further escalations, killing and displacing even more Palestinians. The war, prolonged by Mr. Netanyahu for his political survival, has left a stain on Israel's national compass and deepened its global isolation. In the weeks ahead, France, the U.K. and several other countries are expected to recognise Palestinian sovereignty, while the European Commission has proposed to suspend trade concessions with Israel and sanction extremist Ministers. Yet, Israel, shielded by the U.S., shows little concern. The Trump administration is unlikely to turn up the heat on its closest ally. But Europe should start treating Israel as what it has become – a rogue state with genocidal intent and actions. India, once a champion of the Palestinian cause, has so far refrained from directly criticising the Jewish nation. But it should realise that an uncontrollable, expansionist Israel, blowing international law to smithereens, is not in India's national or regional interests. New Delhi should speak up against the genocide and use its leverage to help bring the war to an end.

3. भू-राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

- **यूरोपीय संघ**: फ्रांस, ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देंगे; यूरोपीय आयोग ने चरमपंथी इस्राइल के मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।
- **यू.एस.**: इज़राइल को बचाना जारी रखता है; वास्तविक दबाव डालने की संभावना नहीं है।
- **इज़राइल**: बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद सैन्य अभियान जारी है।

4. भारत की स्थिति

- ऐतिहासिक रूप से: **फिलिस्तीनी कारण के चैंपियन** (1947 यूएनजीए विभाजन योजना वोट, एनएएम एकजुटता, फिलिस्तीनी राज्य के लिए समर्थन)।
- 1992 के बाद: इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाया, रक्षा और तकनीकी संबंधों को गहरा किया।
- हाल का रुख: युद्धविराम, मानवीय सहायता, "दो-राज्य समाधान" का आह्वान करता है, लेकिन इज़राइल की सीधी आलोचना से बचता है।
- संतुलन अधिनियम:
    - इजरायल के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी।
    - खाड़ी देशों में बड़े प्रवासी + तेल निर्भरता को अरब सद्भावना बनाए रखने की आवश्यकता →।
    - अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने वाली एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखे जाने की इच्छा।

स्टेटिक लिंकेज (प्रीलिम्स)

- **नरसंहार संधि (1948)** – पहली मानवाधिकार संधि, भारत एक पक्ष है।
- **यूएनआरडब्ल्यूए** - फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी।
- **दो-राज्य समाधान** - संयुक्त राष्ट्र संकल्प 181 (1947) के तहत प्रस्तावित।
- **भारत-इजरायल** संबंध: रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा।
- **भारत-फिलिस्तीन** संबंध: 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी गई; संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करता है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **भारत के लिए अवसर:**
    - इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंधों का लाभ उठाने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
    - ग्लोबल साउथ के वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि को बनाए रखें।
    - संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना।
- **चुनौतियाँ**:
    - इजरायल के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी में तनाव का जोखिम।
    - अमेरिका (इज़राइल के सबसे करीबी सहयोगी) को अलग-थलग करने का जोखिम।
    - घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट गाजा में मानवीय संकट की गंभीरता और इजरायल के कार्यों की कानूनी गंभीरता को रेखांकित करती है। **विश्वगुरु** और अंतरराष्ट्रीय कानून का रक्षक बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत के लिए चुप्पी उसकी नैतिक विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। एक संतुलित स्थिति – **दो-राष्ट्र समाधान** के लिए समर्थन की पुष्टि करना, नागरिकों की हत्याओं की निंदा करना और

अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आग्रह करना – भारत के रणनीतिक हितों और नैतिक परंपराओं दोनों के अनुरूप होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : नरसंहार शब्द को पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कानूनी रूप से परिभाषित किया गया था?

a) जिनेवा कन्वेंशन (1949)
b) नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन (1948)
c) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)
d) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम क़ानून (2002)

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : गाजा नरसंहार पर भारत की चुप्पी उसकी नैतिक विरासत और रणनीतिक हितों के बीच तनाव को दर्शाती है। चर्चा करना। (150 शब्द)

Page 09 : GS 2 : Social Justice / Prelims

भारत में, **परिवारों द्वारा आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई)** स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण का प्रमुख तरीका बना हुआ है। जबकि आधिकारिक **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए)** के आंकड़े ओओपीई में गिरावट (2013-14 में 64% से 2021-22 में 39% तक) का सुझाव देते हैं, उपभोक्ता **व्यय सर्वेक्षण (सीईएस-2022-23)** और **सीपीएचएस-सीएमआईई** जैसे वैकल्पिक सर्वेक्षण एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, जो बढ़ते स्वास्थ्य व्यय बोझ को दर्शाते हैं। यह अंतर **स्वास्थ्य व्यय डेटा की सटीकता**, इसके नीतिगत निहितार्थ और परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाई की वास्तविकता के बारे में चिंता पैदा करता है।

प्रमुख वर्तमान घटनाक्रम

1. **एनएचए अनुमान**
   - ओओपीई **64% (2013-14→) से गिरकर 49% (2017-18) → 39% (2021-22) हो** गया।
   - एनएसएस 75वें दौर (2017-18) के **आधार पर** स्वास्थ्य सर्वेक्षण + मूल्य समायोजन के साथ एक्सट्रपलेशन।
2. **एनएचए अनुमानों से संबंधित मुद्दे**
   - एनएसएस 2017-18 में बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की संभावित कम रिपोर्टिंग।
   - COVID-19 सदमे **को बाहर करता है**, जहां घरेलू खर्च में भारी वृद्धि हुई है।

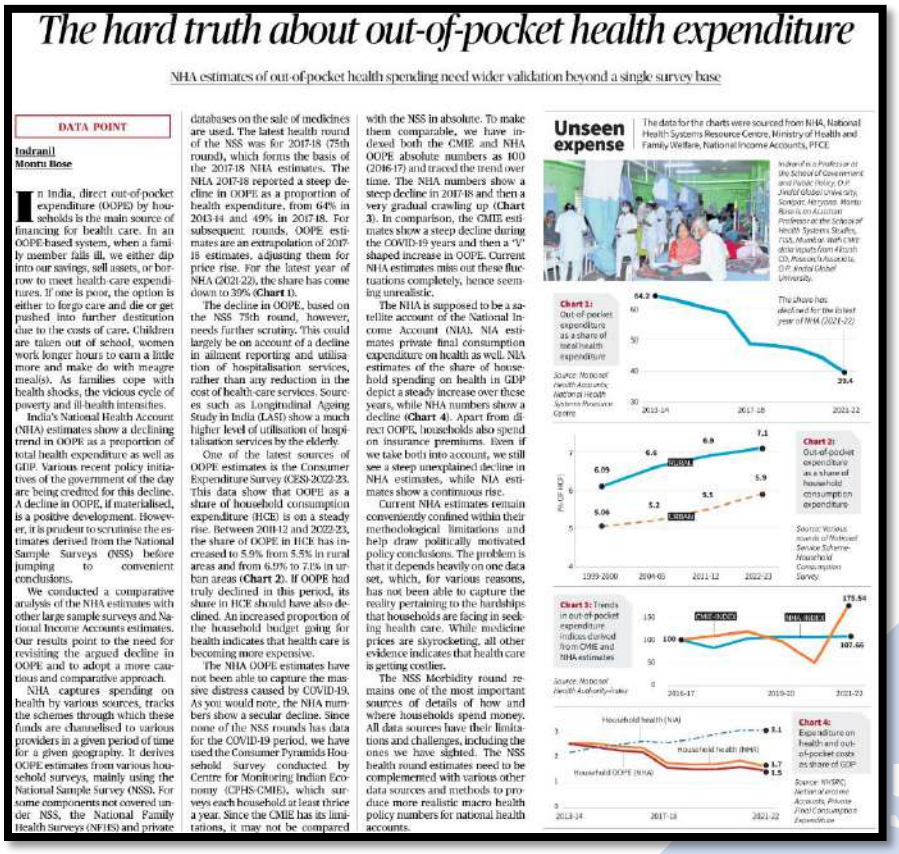

The hard truth about out-of-pocket health expenditure

NHA estimates of out-of-pocket health spending need wider validation beyond a single survey base

DATA POINT

Indranil Montu Bose

In India, direct out-of-pocket expenditure (OOPE) by households is the main source of financing for health care. In an OOPE-based system, when a family member falls ill, we either dip into our savings, sell assets, or borrow to meet health care expenditures. If one is poor, the option is either to forgo care and die or get pushed into further destitution due to the costs of care. Children are taken out of school, women work longer hours to earn a little more and make do with meagre meals). As families cope with health shocks, the vicious cycle of poverty and ill-health intensifies.

India's National Health Account (NHA) estimates show a declining trend in OOPE as a proportion of total health expenditure as well as GDP. Various recent policy initiatives of the government of the day are being credited for this decline. A decline in OOPE, if materialised, is a positive development. However, it is prudent to scrutinise the estimates derived from the National Sample Surveys (NSS) before jumping to convenient conclusions.

We conducted a comparative analysis of the NHA estimates with other large sample surveys and National Income Accounts estimates. Our results point to the need for revisiting the argued decline in OOPE and to adopt a more cautious and comparative approach.

NHA captures spending on health by various sources, tracks the schemes through which these funds are channelised to various providers in a given period of time for a given geography. It derives OOPE estimates from various household surveys, mainly using the National Sample Survey (NSS). For some components not covered under NSS, the National Family Health Surveys (NFHS) and private databases on the sale of medicines are used. The latest health round of the NSS was for 2017-18 (75th round), which forms the basis of the 2017-18 NHA estimates. The NHA 2017-18 reported a steep decline in OOPE as a proportion of health expenditure, from 64% in 2013-14 and 49% in 2017-18. For subsequent rounds, OOPE estimates are an extrapolation of 2017-18 estimates, adjusting them for price rise. For the latest year of NHA (2021-22), the share has come down to 39% (**Chart 1**).

The decline in OOPE, based on the NSS 75th round, however, needs further scrutiny. This could largely be on account of a decline in ailment reporting and utilisation of hospitalisation services, rather than any reduction in the cost of health care services. Sources such as Longitudinal Ageing Study in India (LASI) show a much higher level of utilisation of hospitalisation services by the elderly.

One of the latest sources of OOPE estimates is the Consumer Expenditure Survey (CES-2022-23). This data show that OOPE as a share of household consumption expenditure (HCE) is on a steady rise. Between 2011-12 and 2022-23, the share of OOPE in HCE has increased to 5.9% from 5.5% in rural areas and from 6.9% to 7.1% in urban areas (**Chart 2**). If OOPE had truly declined in this period, its share in HCE should have also declined. An increased proportion of the household budget going for health indicates that health care is becoming more expensive.

The NHA OOPE estimates have not been able to capture the massive distress caused by COVID-19. As you would note, the NHA numbers show a secular decline. Since none of the NSS rounds has data for the COVID-19 period, we have used the Consumer Pyramids Household Survey conducted by Centre for Monitoring Indian Economy (CPHS-CMIE), which surveys each household at least thrice a year. Since the CMIE has its limitations, it may not be compared with the NSS in absolute. To make them comparable, we have indexed both the CMIE and NHA OOPE absolute numbers as 100 (2016-17) and traced the trend over time. The NHA numbers show a steep decline in 2017-18 and then a very gradual crawling up (**Chart 3**). In comparison, the CMIE estimates show a steep decline during the COVID-19 years and then a "V" shaped increase in OOPE. Current NHA estimates miss out these fluctuations completely, hence seeming unrealistic.

The NHA is supposed to be a satellite account of the National Income Account (NIA). NIA estimates private final consumption expenditure on health as well. NIA estimates of the share of household spending on health in GDP depict a steady increase over these years, while NHA numbers show a decline (**Chart 4**). Apart from direct OOPE, households also spend on insurance premiums. Even if we take both into account, we still see a steep unexplained decline in NHA estimates, while NIA estimates show a continuous rise.

Current NHA estimates remain conveniently confined within their methodological limitations and help draw politically motivated policy conclusions. The problem is that it depends heavily on one data set, which, for various reasons, has not been able to capture the reality pertaining to the hardships that households are facing in seeking health care. While medicine prices are skyrocketing, all other evidence indicates that health care is getting costlier.

The NSS Morbidity round remains one of the most important sources of details of how and where households spend money. All data sources have their limitations and challenges, including the ones we have sighted. The NSS health round estimates need to be complemented with various other data sources and methods to produce more realistic macro health policy numbers for national health accounts.

Unseen expense

The data for the charts were sourced from NHA, National Health Systems Resource Centre, Ministry of Health and Family Welfare, National Income Accounts, PFCE

Chart 1: Out-of-pocket expenditure as a share of total health expenditure

Chart 2: Out-of-pocket expenditure as a share of household consumption expenditure

Chart 3: Trends in out-of-pocket expenditure indices derived from CMIE and NHA estimates

Chart 4: Expenditure on health and out-of-pocket costs as share of GDP

- कार्यप्रणाली एकल डेटा स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

3. **वैकल्पिक डेटा स्रोत**
    - **सीईएस 2022-23**: घरेलू खपत में ओओपीई की हिस्सेदारी ↑ (ग्रामीण: 5.5% → 5.9%; शहरी: 6.9% → 7.1%)।
    - **एलएएसआई**: एनएसएस के सुझाव की तुलना में बुजुर्गों में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या अधिक है।
    - **CPHS-CMIE**: "V-आकार" की प्रवृत्ति दिखाता है - COVID के दौरान OOPE में तेज गिरावट, इसके बाद NHA की सुचारू गिरावट के विपरीत।
    - **NIA का अनुमान**: GDP के % के रूप में घरेलू स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहा है, जो NHA की गिरावट के विपरीत है।

स्टेटिक लिंकेज (प्रीलिम्स पॉइंटर्स)

- **OOPE परिभाषा**: स्वास्थ्य (डॉक्टर की फीस, दवाएं, निदान, अस्पताल के बिल) के लिए परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष खर्च बीमा या सरकारी योजनाओं द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।
- **एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा):** स्रोत, वित्तपोषण योजना, प्रदाता, कार्य → स्वास्थ्य व्यय के प्रवाह को ट्रैक करता है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस):** रुग्णता और व्यय के लिए प्रमुख डेटा स्रोत।
- **आयुष्मान भारत (2018):** फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य प्रति परिवार ₹5 लाख का बीमा प्रदान करके ओओपीई को कम करना है।
- **स्वास्थ्य वित्तपोषण लक्ष्य**: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) – सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंच जाएगा।

मुख्य आयाम

स्वास्थ्य और शासन

- उच्च ओओपीई → **विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय** → गरीबी के जाल में।
- भारत का स्वास्थ्य वित्तपोषण अभी भी विषम है: सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का ~1.3% (वैश्विक औसत ~6% की तुलना में कम)।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की कमी → निजी क्षेत्र पर भारी निर्भरता।

अर्थव्यवस्था और डेटा अखंडता

- नीति निर्माण में आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता।
- नीति में शालीनता **का जोखिम** यदि डेटा सुधार का सुझाव देता है जो वास्तविक नहीं है।
- डेटा के त्रिकोणीकरण **की आवश्यकता**: एनएचए + सीईएस + एलएएसआई + सीएमआईई।

नैतिकता और निबंध

- स्वास्थ्य एक सामाजिक न्याय के मुद्दे **के रूप में**।
- गरीब परिवारों का इलाज के लिए संपत्ति बेचना या शिक्षा देना राज्य के लिए नैतिक चुनौती →।
- सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा **सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेदारी**।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **सकारात्मक**: आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, कुछ राज्यों में मुफ्त दवाओं जैसी सरकारी योजनाओं ने मदद की है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

- **चिंताएँ**:
  - एनएचए में ओओपीई में गिरावट **सांख्यिकीय भ्रम हो सकती है**।
  - स्वास्थ्य देखभाल की वास्तविक लागत बढ़ रही है (दवाएं, निदान, निजी अस्पताल में भर्ती)।
  - आधिकारिक संख्या में COVID-19 तनाव गायब है।
- **आगे की राह:**
  - एनएचए के लिए बहु-स्रोत डेटा त्रिकोणीकरण।
  - समय-समय पर एनएसएस स्वास्थ्य दौर (हर 3 साल में)।
  - महंगी निजी देखभाल पर निर्भरता कम करने के लिए **सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे** को मजबूत करना।
  - अस्पताल में भर्ती होने (ओपीडी, दवाओं) से परे बीमा **कवरेज** का विस्तार करें।

निष्कर्ष

एनएचए के अनुसार, भारत के ओओपीई में गिरावट अन्य सर्वेक्षणों के साथ क्रॉस-वेरिफाई करने पर पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। यदि इस तरह के आंकड़ों को ठीक नहीं किया जाता है, तो **झूठी आशावाद पैदा** करने और परिवारों के वास्तविक वित्तीय संघर्षों को छिपाने का जोखिम होता है। भारत को **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** प्राप्त करने और स्वास्थ्य झटकों के कारण **परिवारों को गरीबी से बचाने** के लिए, इसे **डेटा विश्वसनीयता में सुधार करना** चाहिए और सस्ती **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना** चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ओओपीई से तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवारों द्वारा बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के किए गए प्रत्यक्ष भुगतान से है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2021-22 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में OOPE की हिस्सेदारी घटकर लगभग 39% हो गई है।
3. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) 2022-23 से पता चलता है कि 2011-12 के बाद से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू उपभोग व्यय में ओओपीई की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: क)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय का अनुमान लगाने के लिए केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों पर निर्भर रहने की सीमाएं क्या हैं? स्वास्थ्य व्यय डेटा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना। **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

दैनिक समाचार विश्लेषण

Let Geiger counters, not guesses, shape Iran actions

A new nuclear crisis is taking shape. After the United States's strikes on Iran's underground nuclear site at Fordow, in June 2025, Britain, France, and Germany (E3), on August 28, triggered the "snapback" clause of the 2015 nuclear deal citing violations by Tehran. The world has not much time to choose between diplomacy and escalation.

If this window closes without agreement, the United Nations will restore earlier measures that call for a halt to enrichment, tighten controls on arms transfers, restrict finance and shipping, and re-designate individuals linked to Iran's nuclear and missile programmes.

The stakes are global. Iran rejects the move as unlawful. Washington sees it as a test of non-proliferation. Europe views multilateral commitments on trial. Russia and China seek delay and leverage. Israel and the Gulf states weigh warning times and war risks. Oil importers watch prices. Shipping companies reassess insurance. Banks calculate exposure. For India, the anxieties are sharper still. Its extended neighbourhood must remain stable, oil must keep flowing through the Strait of Hormuz, and the safety of eight million Indian citizens in West Asia must be ensured.

The vacuum of facts

These concerns are magnified by the absence of verified information. Since the strikes on Iranian facilities, no one has walked the rubble with a dosimeter or tested a coolant line. The International Atomic Energy Agency (IAEA) staff left Iran after its Parliament passed legislation halting cooperation without approval from the Supreme National Security Council. Rumour has replaced measurement. Every capital has drawn its own conclusions while global attention shifted elsewhere.

Syed Akbaruddin

was an international civil servant at the International Atomic Energy Agency (IAEA) from 2006 to 2011

India can take the lead in ensuring technical IAEA access to Iran's nuclear programme as it will anchor negotiations to verifiable data

IAEA access is not a formality but the hinge of diplomacy. Verification replaces speculation with facts, sets a baseline on Iranian stockpiles, and anchors negotiations to data, not fears. Regular IAEA updates on Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant, under Russian control, calmed jittery markets. A comparable presence in Iran could steady expectations and reduce volatility. If verification is framed as a sovereign choice, rather than a concession, it would strengthen Iran's claim that the programme is civilian while upholding the non-proliferation bargain.

Yet, Tehran's reservations are not unfounded. Iranian officials argue that sovereignty and security outweigh treaty obligations. They fear inspectors may, even unintentionally, enable targeting of sensitive sites. This is not paranoia. Strikes by Israel and the U.S. in the past closely followed IAEA disclosures. Such episodes have hardened parliamentary resistance. There is also the calculus of leverage. Revealing what survives of the programme could weaken Iran's hand in bargaining with Washington.

Since the E3 triggered its snapback, some Iranian legislators have urged withdrawal from the Nuclear Non Proliferation Treaty. That would strip the IAEA of legal authority to inspect Iranian sites. The crisis would then enter uncharted territory with sanctions hardening and the military option returning to the fore.

Where India fits in

India cannot stand aside. As a long-standing member of the IAEA Board, with ties across divides, it is well placed to assist. As a part of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), India, at the Tianjin summit, has joined other nations in condemning the military strikes by Israel and the U.S. against Iran.

Within the SCO and BRICS – both of which include Iran – India can support a diplomatic call to restore technical IAEA access in a form that protects operational details while ensuring transparency. If framed as a sovereign choice by Tehran, and backed by the Global South, it may gain Iranian approval. India can also contribute technical capacity. Its IAEA-certified Tarapur facility could handle sample analysis under safeguards, showing that responsible stakeholders can provide practical support in moments of crisis. These contributions would not make headlines, but they could shift the balance toward diplomacy at a time when the risk of escalation is high.

A closing window

The window for diplomacy is narrowing fast. By allowing IAEA inspectors into Bushehr to monitor the refuelling of the nuclear power plant last month, Iran has offered a small opening. Also, last week, on September 9, 2025, , the IAEA and Iran signed an agreement in Cairo, Egypt. If this extends to bombed sites, the E3 may respond by pausing the snapback. Such choices could shift the momentum back to diplomacy. The alternative is grim – sanctions, standoffs, and a cycle of strike and counterstrike.

For India, the choice is clear. Backing verification protects its interests in West Asia, its citizens abroad, and its energy security. It also marks India as a responsible global power. The way forward is simple. It is time to let Geiger counters, and not guesses, decide Iran's nuclear programme.

GS. Paper 02 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य अभ्यास प्रश्न: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के साथ अप्रसार उद्देश्यों को संतुलित करने में आईएईए बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत की भूमिका और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना।**(150 शब्द)**

संदर्भ:

फोर्डो परमाणु स्थल (जून 2025) पर अमेरिकी हमलों और 3 अगस्त, 28 को E28 (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) द्वारा **"स्नैपबैक क्लॉज"** के ट्रिगर होने के बाद ईरान के साथ परमाणु गतिरोध तेज हो गया है । आईएईए के निरीक्षकों के ईरान से बाहर होने के कारण, सत्यापित डेटा गायब है, जिससे गलत अनुमान का खतरा बढ़ गया है। यह संकट **अप्रसार व्यवस्था**, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा लेता है – जो भारत के लिए सीधी चिंता के मुद्दे हैं।

करेंट अफेयर्स हाइलाइट्स

1. परमाणु संकट

- **E3 स्नैपबैक क्लॉज**: यदि ईरान 2015 JCPOA (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) का उल्लंघन करता है तो प्रतिबंधों को बहाल करता है।
- यदि लागू किया जाता है: संवर्धन, हथियार हस्तांतरण नियंत्रण, शिपिंग प्रतिबंध, वित्तीय प्रतिबंधों पर प्रतिबंध।
- ईरान ने वैधता से इनकार किया; **परमाणु अप्रसार संधि से** हटने की धमकी दी।

2. सत्यापन अंतर

- ईरान की संसद में मतदान के बाद आईएईए के निरीक्षकों को निष्कासित कर दिया गया।
- अफवाहें और अटकलें सत्यापित डेटा की जगह ले रही हैं।
- पिछली मिसाल: ज़ापोरिज़्ज़िया (यूक्रेन) में IAEA की पहुंच ने बाजारों को शांत किया; ईरान में अनुपस्थिति अस्थिरता को बढ़ावा देती है।

3. ईरान की दुविधा

- संप्रभुता के उल्लंघन का डर - पिछले अमेरिका/इज़राइल हमलों ने IAEA के खुलासे के बाद किया।
- सौदेबाजी का लाभ - कार्यक्रम की स्थिति को छिपाने से बातचीत में मदद मिलती है।
- आंतरिक बहस: कुछ सांसदों ने एनपीटी को वापस लेने का आग्रह किया → आईएईए के अधिकार को छीन लेंगे।

4. भारत की हिस्सेदारी

- **ऊर्जा सुरक्षा**: पश्चिम एशियाई तेल पर निर्भरता; होर्मुज जलडमरूमध्य स्थिरता महत्वपूर्ण।
- **प्रवासी सुरक्षा**: खाड़ी में 8 मिलियन भारतीय।
- **क्षेत्रीय स्थिरता**: वृद्धि व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है।
- **आईएईए की भूमिका**: भारत तकनीकी विश्वसनीयता (तारापुर सुविधा प्रमाणित) के साथ एक बोर्ड का सदस्य है।

5. राजनयिक उद्घाटन

- 9 सितंबर, 2025: निरीक्षकों के संभावित पुन: प्रवेश के → काहिरा में IAEA-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।
- ईरान ने बुशहर निगरानी (अगस्त 2025) को छोटे सद्भावना संकेत → अनुमति दी।
- यदि बमबारी वाली साइटों तक विस्तारित किया जाता है, तो E3 स्नैपबैक को रोक सकता है और कूटनीति को पुनर्जीवित कर सकता है।

स्थैतिक संबंध

- **जेसीपीओए (2015):** ईरान + पी 5 + 1 (यूएस, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी) + ईयू। ट्रंप के कार्यकाल में 2018 में अमेरिका ने वापसी की थी।
- **स्नैपबैक तंत्र**: वीटो के बिना संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की अनुमति देता है, यदि जेसीपीओए उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।
- **आईएईए:** वियना स्थित स्वायत्त एजेंसी (1957), परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग की पुष्टि करती है।
- **एनपीटी (1970):** भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है; ईरान है। निकासी = अनुच्छेद X अधिकार।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य**: ~ 20% दुनिया का पेट्रोलियम होकर गुजरता है।

मुख्य प्रासंगिकता

दैनिक समाचार विश्लेषण

आईआर

- भारत का संतुलन कार्य: अमेरिका, इज़राइल, खाड़ी बनाम ईरान के साथ पारंपरिक संबंधों के साथ रणनीतिक संबंध।
- ग्लोबल साउथ लीडरशिप: कूटनीति के लिए एससीओ/ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

सुरक्षा/अर्थव्यवस्था

- ऊर्जा निर्भरता: तेल आयात, शिपिंग बीमा, रुपये की स्थिरता।
- अप्रसार: भारत एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में, आईएईए सत्यापन का समर्थन करता है।

आईआर में नैतिकता

- पारदर्शिता बनाम संप्रभुता: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सत्यापन के अधिकार के साथ ईरान की सुरक्षा के अधिकार को संतुलित करना।
- संस्थानों में विश्वास: एकतरफा हमलों पर बहुपक्षवाद (आईएईए, यूएन) को बनाए रखना।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **अवसर**:
  - भारत ईरान की संप्रभु पसंद के रूप में तैयार किए गए एक तकनीकी सत्यापन तंत्र का प्रस्ताव कर सकता है।
  - नमूना विश्लेषण (तारापुर) को संभालने के लिए IAEA में अपनी विश्वसनीयता का उपयोग कर सकता है।
  - मध्यस्थता से ग्लोबल साउथ में भारत के लिए नेतृत्व का अवसर।
- **चुनौतियाँ**:
  - अमेरिका और इजरायल को भारत की तटस्थता पर संदेह है।
  - ईरान का पक्ष लेते हुए देखा जाए तो खाड़ी के भागीदारों को अलग-थलग करने का खतरा है।
  - प्रतिबंधों और तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए आर्थिक जोखिम।

निष्कर्ष

ईरान परमाणु संकट चरम पर है। IAEA सत्यापन के बिना, अटकलों से तनाव बढ़ने का जोखिम है। भारत को अपने **ऊर्जा हितों, प्रवासी भारतीयों की चिंताओं और बहुपक्षीय साख** के साथ, तथ्यों में निहित कूटनीति का समर्थन करना चाहिए, न कि भय में। ईरान के लिए एक तकनीकी, संप्रभु विकल्प के रूप में आईएईए के निरीक्षण का समर्थन करने से भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी और एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी छवि मजबूत होगी।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)
DURATION : 7 MONTH
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**